

सिविल निर्देश
न्यायमूर्ति एच.आर. सोढ़ी के समक्ष
इन्द्र, - याचिकाकर्ता
बनाम

गुरदित सिंह, - प्रतिवादी

1970 का सिविल संदर्भ संख्या 1

8 फरवरी, 1971

पंजाब किरायेदारी अधिनियम (1887 का XVI) - धारा 77 (3) (के) - साक्ष्य अधिनियम (1872 का I) - धारा 115 - वादी अपने हिस्से की उपज की वसूली के लिए राजस्व न्यायालय में मुकदमा दायर करता है - प्रतिवादी मुकदमे की सुनवाई के लिए राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति जताता है - सिविल कोर्ट में दायर मुकदमा - सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति करने वाले प्रतिवादी भी केवल राजस्व न्यायालय द्वारा मुकदमे की पैरवी करते हैं - ऐसे प्रतिवादी को याचिका उठाने के लिए रोका गया है।

यह माना गया कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 115 के तहत प्रतिनिधित्व द्वारा एस्टोपेल का सिद्धांत, क्योंकि यह समानता और अच्छे विवेक पर आधारित है, विभिन्न प्रकार के मामलों में लागू करने में सक्षम है। यह न्याय का एक अच्छी तरह से स्थापित नियम है कि किसी कार्यवाही में एक पक्ष को अनुमति देने और पुनः पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बेशक, सिद्धांत किसी कानून के प्रावधानों के खिलाफ लागू नहीं होता है या जहां यह मौजूद नहीं है, वहां अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं कर सकता है, लेकिन साथ ही एक कार्यवाही के लिए एक पक्ष समानता और अच्छे विवेक में एक स्थिति स्थापित नहीं कर सकता है जो पहले से ही उसके द्वारा लिया गया है और जिस पर विपरीत पक्ष पहले ही कार्रवाई कर चुका है। जहां किसी विवाद का संज्ञान लेने के लिए किसी न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथ्यों का पता लगाने पर निर्भर करता है और उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति की जाती है, तो उस पक्ष के लिए, जब आपत्ति प्रबल हो जाती है, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में फिर से आपत्ति उठाने के लिए खुला नहीं है, जो उसकी पूर्व आपत्ति के अनुसार, कारण की कोशिश करने का अधिकार क्षेत्र था। इसलिए जब कोई वादी अपने हिस्से की उपज की वसूली के लिए राजस्व न्यायालय में मुकदमा दायर करता है, तो प्रतिवादी वाद की सुनवाई करने के लिए राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति करता है, आपत्ति प्रबल होती है और वाद को सिविल कोर्ट में दायर करने के लिए वापस कर दिया जाता है, प्रतिवादी को इस दलील पर सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति करने से रोका दिया जाता है कि मुकदमा केवल राजस्व न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य है। इस तरह के मामले में एस्टोपेल के सिद्धांत का एक आवेदन एक सिविल कोर्ट को अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करेगा, बल्कि केवल प्रतिवादी को उन तथ्यों की सच्चाई से इनकार करने से रोकेगा जिन्हें उसने राजस्व न्यायालय के समक्ष पहले स्वीकार किया था, और जिसके आधार पर वाद वापस कर दिया गया था। प्रतिवादी को सिविल और राजस्व न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के बारे में असंगत याचिकाओं को लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(पैरा 5)

पंजाब किरायेदारी अधिनियम (1887 का अधिनियम XVI) की धारा 99 के तहत 18 फरवरी, 1969 को अंबाला के वरिष्ठ उप-न्यायाधीश द्वारा जिला न्यायाधीश, अंबाला के माध्यम से क्षेत्राधिकार के प्रश्न के निर्णय के लिए संदर्भ दिया गया।

"क्या मामला सिविल कोर्ट या राजस्व न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य है".

याचिकाकर्ता के लिए कोई नहीं।

उत्तरदाताओं के लिए कोई नहीं।

JUDGMENT

न्यायमूर्ति एच.आर.सोढ़ी—(1) अधिकार क्षेत्र के प्रश्न को उठाते हुए यह संदर्भ पंजाब किरायेदारी अधिनियम (1887 का अधिनियम XVI) की धारा 99 के तहत इस न्यायालय को दिया गया है, जिसे बाद में अधिनियम कहा जाता है। संदर्भ का कारण बनने वाले तथ्य विवाद में नहीं हैं

(2) इंदर ने दावा किया कि उसने कुछ फसल के लिए प्रतिवादी के साथ सांझी (भागीदार खेती) के रूप में काम किया था, लेकिन खेती के तहत भूमि से उपज के 1/5 वें हिस्से का भुगतान नहीं किया गया था। अपने हिस्से की वसूली के लिए एक मुकदमा शुरू में 30 मई, 1968 को राजस्व न्यायालय (सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी की अदालत, अंबाला शहर) में दायर किया गया था। मुकदमे का एक नोटिस प्रतिवादी को दिया गया था, जिसने अपने लिखित बयान में प्रारंभिक आपत्ति जताई थी कि मुकदमा राजस्व अदालत में नहीं है। इस संबंध में उनके द्वारा अधिनियम की धारा 77 पर भरोसा किया गया था, यह दलील दी गई थी कि यह मामला धारा 77 (3) में संदर्भित पहले समूह के खंड (के) के तहत नहीं आता है। धारा 77 (3) उन मामलों की एक सूची देती है जिन्हें केवल राजस्व न्यायालयों द्वारा स्थापित, सुना और निर्धारित किया जा सकता है और कोई अन्य न्यायालय उसमें उत्पन्न विवाद का संज्ञान नहीं ले सकता है। इस खंड से संबंधित उद्धरण को संदर्भ की सुविधा के लिए यहां पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है: –

“77. (3) राजस्व न्यायालयों द्वारा निम्नलिखित वाद की स्थापना और सुनवाई तथा निर्धारण किया जाएगा और कोई अन्य न्यायालय ऐसे किसी विवाद या मामले का संज्ञान नहीं लेगा जिसके संबंध में ऐसा कोई वाद स्थापित किया जा सकता है :-

*	*	*	*	*
*	•	◆	*	*
पहला समूह				
*	«	*	◆	* •
*	*	◆'	*	*

(k) किसी संपत्ति में सह-हिस्सेदार द्वारा मुकदमा या उसके मुनाफे के हिस्से के लिए या खातों के निपटान के लिए;

(3) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई मुकदमा उपरोक्त खंड के दायरे में आता है, पक्षकारों द्वारा दिए गए तथ्यों पर यह निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या उपज के अपने हिस्से के लिए मुकदमा करने वाले वादी को, उसके द्वारा कथित परिस्थितियों में,

कानून के तहत संपत्ति या होल्डिंग में सह-हिस्सेदार के रूप में माना जा सकता है। इस मामले में वादी ने प्रारंभिक आपत्ति के बल को स्वीकार कर लिया और स्वीकार किया कि उनके द्वारा तय किया गया मुकदमा, राजस्व न्यायालय के संज्ञान में नहीं था, और उचित अदालत में प्रस्तुत करने के लिए वाद को वापस करने के लिए कहा गया था, जिसका अर्थ है सिविल अदालत। 30 अक्टूबर, 1968 को किए गए सहायक कलेक्टर के आदेश द्वारा वादपत्र को तदनुसार वापस कर दिया गया था। वादी ने तब एक सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया, जहां प्रतिवादी ने फिर से आपत्ति जताई कि उक्त न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और मुकदमा केवल राजस्व न्यायालय द्वारा संज्ञेय था। सिविल कोर्ट ने आपत्ति पर विचार किया और निम्नलिखित शब्दों में एक प्रारंभिक मुद्दा तैयार किया -

"क्या मुकदमा सिविल कोर्ट द्वारा सुनवाई योग्य है।

(4) सुंदर सिंह बनाम केसर सिंह (1) के रूप में रिपोर्ट किए गए पंजाब मुख्य न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा करते हुए पार्टियों और सिविल कोर्ट द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किया गया था, जिसके बाद बख्शीश सिंह बनाम करतार सिंह (2) में इस अदालत की एक खंडपीठ द्वारा अनुसरण किया गया था, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मुकदमा केवल राजस्व न्यायालय द्वारा संज्ञेय था। यहां वादी के वकील ने फिर से स्वीकार किया कि मुकदमा राजस्व अदालत में है और बाद की अदालत में प्रस्तुत करने के लिए उन्हें वाद वापस करने की प्रार्थना की। वाद को वापस करने के बजाय, सिविल कोर्ट ने इस न्यायालय को वर्तमान संदर्भ दिया था, यह विचार था कि वाद को वापस किया जा सकता है यदि मुकदमा पहली बार उस न्यायालय में स्थापित किया गया था। इसने 30 अक्टूबर, 1968 को पारित सहायक कलेक्टर की अदालत के आदेश का संज्ञान लिया, जिसके तहत उक्त न्यायालय ने पहले ही इस आधार पर वाद वापस कर दिया था कि मुकदमा उस अदालत में नहीं है।

(5) अब विचार के लिए एकमात्र प्रश्न यह है कि किस न्यायालय को मुकदमे की सुनवाई करनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुख्य न्यायालय ने *सुंदर सिंह के मामले* (1), (सुप्रा) में कहा कि प्रतिवादी के स्वामित्व वाली और एक समझौते के तहत वादी के साथ साझेदारी में खेती की गई कुछ भूमि की उपज में हिस्सेदारी के लिए मुकदमा धारा 77 (3) (के) के अर्थ के भीतर होल्डिंग के मुनाफे में हिस्सेदारी के लिए सह-हिस्सेदार द्वारा मुकदमा है और राजस्व न्यायालय द्वारा संज्ञेय था और इस दृष्टिकोण का पालन किया गया था। *बख्शीश सिंह के मामले* (2), (सुप्रा) में इस न्यायालय की खंडपीठ ने इस आधार पर अधिक कहा कि इसे परेशान करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा क्योंकि यह लंबे समय से खड़ा था, लेकिन जो भी हो, उन निर्णयों की शुद्धता पर कोई राय व्यक्त करना मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं अकेले बैठकर इससे बंधा हुआ हूँ।

हालांकि, तथ्य यह है कि प्रतिवादी ने राजस्व न्यायालय के समक्ष यह स्थिति रखी थी कि मुकदमा उस न्यायालय द्वारा संज्ञेय नहीं था और राजस्व न्यायालय द्वारा इस याचिका को बरकरार रखे जाने के परिणामस्वरूप वादी को सिविल कोर्ट में प्रस्तुति के लिए वादी को वापस कर दिया गया था। जब मामला सिविल कोर्ट में गया, तो प्रतिवादी ने वहां अधिकार क्षेत्र का सवाल उठाया और साथ ही असंगत स्थिति भी उठाई कि मुकदमा केवल राजस्व

न्यायालय में हो सकता है। मेरी राय में, यह एक प्रकार का मामला है जहां प्रतिवादी को उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में सिविल कोर्ट में याचिका उठाने से रोका जाना चाहिए और मुकदमे की सुनवाई वहां की जानी चाहिए। प्रतिनिधित्व द्वारा एस्टोपेल का सिद्धांत क्योंकि यह समानता और अच्छे विवेक पर आधारित है, विभिन्न प्रकार के मामलों में लागू करने में सक्षम है। यह न्याय का एक अच्छी तरह से स्थापित नियम है कि किसी कार्यवाही में एक पक्ष को अनुमति देने और पुनः पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बेशक, सिद्धांत किसी कानून के प्रावधानों के खिलाफ लागू नहीं होता है या जहां यह मौजूद नहीं है, वहां अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं कर सकता है, लेकिन साथ ही एक कार्यवाही के लिए एक पक्ष समानता और अच्छे विवेक में एक स्थिति स्थापित नहीं कर सकता है जो पहले से ही उसके द्वारा लिया गया है और जिस पर विपरीत पक्ष पहले ही कार्रवाई कर चुका है। यह एक पक्ष को तेजी से और ढीला खेलने की अनुमति देने के समान होगा यदि वह एक ही कारण से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में असंगत याचिकाओं पर विचार करता है। वर्तमान अधिकार क्षेत्र की अंतर्निहित कमी का मामला नहीं है, लेकिन तथ्यों को शामिल किया गया था, जिस पर इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए निर्णय आवश्यक था कि वादी एक संपत्ति या होल्डिंग में सह-हिस्सेदार था या नहीं। जहां किसी विवाद का संज्ञान लेने के लिए किसी न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथ्यों का पता लगाने पर निर्भर करता है और उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति की जाती है, तो उस पक्ष के लिए, जब आपत्ति प्रबल हो जाती है, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में फिर से आपत्ति उठाने के लिए खुला नहीं है, जो उसकी पूर्व आपत्ति के अनुसार, कारण की कोशिश करने का अधिकार क्षेत्र था। इस तरह के मामले में एस्टोपेल के सिद्धांत का एक आवेदन एक सिविल कोर्ट को अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करेगा, बल्कि केवल प्रतिवादी को उन तथ्यों की सच्चाई से इनकार करने से रोकेगा जिन्हें उसने राजस्व न्यायालय के समक्ष पहले स्वीकार किया था, और जिसके आधार पर वाद वापस कर दिया गया था।

(6) मैंने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसे महादेव सिंह बनाम पुदई सिंह (3) मामले में अवध उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा की गई टिप्पणी और हकीम सैयद शाह खुर्शीद अली बनाम कम्मर तिरहुत डिवीजन और एक अन्य (4) मामले में पटना उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी से समर्थन मिलता है। महादेव सिंह के मामले (3) में जो स्थिति उत्पन्न हुई, वह लगभग वैसी ही थी जैसी पहले थी। वादी ने राजस्व न्यायालय में वाद भूमि के कब्जे की वसूली के लिए कार्यवाही की। महादेव सिंह का बचाव यह था कि राजस्व न्यायालय के पास उस दावे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और उनके बचाव को स्वीकार कर लिया गया था। वादी ने तब सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया और प्रतिवादी ने फिर से दलील दी कि मुकदमा सिविल कोर्ट द्वारा संज्ञेय नहीं है। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में मामला आने पर, यह माना गया कि प्रतिवादी को सिविल कोर्ट में अधिकार क्षेत्र की दलील उठाने से रोका गया था। हकीम सैयद शाह खुर्शीद आल के मामले (4) में भी अनुपात इसी तर्ज पर है। प्रतिवादी के खिलाफ बेदखली के लिए लाए गए मुकदमे को सिविल कोर्ट ने इस आपत्ति पर खारिज कर दिया था कि किराया नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण इसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। जब किराया नियंत्रण अधिकारियों के समक्ष निष्कासन की इसी तरह की राहत मांगी गई थी, तो इसे हाउस कंट्रोलर और कलेक्टर

द्वारा अपील पर दिया गया था, लेकिन आयुक्त ने पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए निष्कासन के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि हाउस कंट्रोलर का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि किराया नियंत्रण अधिकारियों ने किरायेदार को असंगत दलीलें देने की अनुमति देने की कानूनी गलती की थी और इस तरह किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत निहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से इनकार कर दिया।

(7) पूर्वगामी कारणों के लिए, मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्तमान मामले में प्रतिवादी को कोई असंगत याचिकाएं उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और मुकदमा सिविल कोर्ट में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए, संदर्भ का उत्तर ऊपर के रूप में दिया गया है।

(8) यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सेवा के बावजूद, कोई भी पक्ष इस अदालत में उपस्थित नहीं हुआ और मुझे किसी भी वकील से सहायता का लाभ नहीं मिल सका।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

जोगिंद्र जांगड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हथीन, हरियाणा